प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 9 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 25 – 04 मार्च 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या यह प्रस्तावित औद्योगिक निवेश धरातल पर उतर पायेगा या जुमला होकर ही रह जायेगा

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी विभिन्न उद्योगपत्तियों के साथ 159 एमओयू साईन करके प्रदेश में 17356 करोड़ का निवेश आने और 40,000 लोगों को रोजगार मिलने का एक बड़ा सपना प्रदेश की जनता करो परोसा है। यह सपना ज़मीन पर आकार ले पायेगा या जुमला होकर ही रह जायेगा। यह सवाल अभी से उठने लग पड़ा है। यह सवाल उद्योग विभाग के उस पत्र से उठा है जो विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा सारे प्रशासकीय सचिवों को सात फरवरी को लिखा गया है। इस पत्र में सचिवों से कहा गया है "You are, therefore, requested to take up with and invite the investors of projects which are in pipeline and/or in which EC or permission under section-118 of H.P. Tenancy and Land Reform Act stand signed/ issued and request them to participate in the aforesaid 'MOU signing ceremony'. A copy of the suggested MoU is enclosed for your reference.

You are also requested to inform the number and details of MoUs proposed to be signed in the by your department/organization, to this Office within a week.

This Memorandum of Understanding is made to facilitate M/s. for establishment of the aforesaid project in Himachal Pradesh in a time bound manner.

This MOU indicates the intention of the investor in brief about the proposed industry and the possible facilitation to be extended by the state Government and shall remain valid for a maximum period of 12 (twelve) months from the date of entering into MOU unless otherwise extended by second party. No separate notice will be required to be issued for this."

इस पत्र में सरकार द्वारा संभावित निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिये यथा संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। लेकिन इस निवेशक मीट को जिस तरह से प्रचारित किया गया है उससे यह संदेश दिया गया है कि इतना निवेश प्रदेश को मिल गया है और 40000 लोगों को रोजगार मिलने ही वाला है। इस निवेशक मीट पर सरकार का खर्च हुआ है। आगे जो ऐसी ही मीट प्रस्तावित है उस पर भी खर्च होगा। प्रदेश में 1977 से औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित होते आये हैं। इन क्षेत्रों में उद्योग भी स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों को हर तरह का सहयोग दिया गया है। प्रदेश का वित्त निगम, एसआईडीसी, जी आईसी और खादी एवम् ग्रामीण उद्योग बोर्ड, यह सारे अदारे इन उद्योगों को सहायता देते रहे हैं। लेकिन आज इन सारे अदारों की अपनी सेहत भी नाजुक होने के कगार पर पंहुच गयी है। बल्कि कुछ तो कभी भी बन्द होने की हालत तक पंहुच चुके हैं। लेकिन इस सबके बावजूद आज यदि यह आंकलन किया जाये कि कब कितने उद्योग स्थापित हुए और उनमें से अब कितने यहां चल रहे हैं तो शायद यह आंकड़े चौंकाने वाले होंगे।

हिमाचल में निवेशकों के आकर्षण का सबसे बड़ा कारण था यहां पर सस्ती और निर्बाध बिजली। क्योंकि आद्यौगिक क्षेत्र में हिमाचल की पहचान बिजली उत्पादक राज्य के रूप में देशभर में प्रचारित और प्रसारित थी। लेकिन इस निवेशक मीट के बाद प्रदेश में जिस तरह से बिजली के रेट बढ़ाये गये हैं। उनको लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी संगठनों से लेकर आम आदमी तक इस पर रोष प्रकट कर रहा है और हो सकता है कि इसके लिये आन्दोलन की नौबत आ जाये। ऐसे में यह सीधा सवाल उठता है कि क्या इन बढ़ी हुई बिजली दरों का सामने रखकर निवेशक हिमाचल आने का रूख करेंगे। क्योंकि किसी भी उद्योग के लिये यह आवश्यक होता है कि जहां वह स्थापित हो रहा है वहां क्या उसके उत्पाद का पर्याप्त उपभोक्ता है। यदि उपभोक्ता नही है तो क्या उत्पादन के लिये सस्ते संसाधन हैं। क्या उद्योग विभाग ने इन बुनियादी आवश्यकताओं का कोई आंकलन करवाया है? शायद नहीं।

जो एम ओ यू साईन हुए हैं उनमें सिरमौर में प्रस्तावित सीमेन्ट उद्योग को लेकर भी एक है। जबकि प्रदेश सरकार ने जुलाई 2006 में चौपाल के गुम्मा – रोहाना में एक प्राईवेट कंपनी के साथ दो मिलियन टन क्लींकर और एक मिलियन टन सीमेन्ट के लिये एम ओ यू साईन किया था। इस एमओयू के मुताबिक कंपनी को माईनिंग लीज, फोरेस्ट क्लीयरैन्स, पर्यावरण क्लीयरैन्स आदि सबकुछ अपने खर्चे से हासिल करना था। उद्योग विभाग के जियोलोजिक विंग को संभावित लाईम स्टोन के रिर्जव आदि का आंकलन कंपनी के आग्रह और खर्च पर करना था। इसी तरह का एक एमओयू सितम्बर 2009 में सुन्दर नगर के लिये साईन हुआ था। दोनो जगह विभाग ने लाईम स्टोन के भण्डार का आंकलन करने के लिये अपनी मशीनरी और कर्मचारी लगा दिये थे। इस काम पर विभाग का करीब 2.77 करोड़ रूपया खर्च हुआ है। जबकि दोनो कंपनियों से विभाग को केवल 89 लाख ही मिल पाये हैं। इन कंपनीयों को फोरेस्ट आदि की क्लीयरैन्स नही मिल पायी है और इस कारण से अगस्त 2017 से इन्होंने काम बन्द कर दिया है। जिस समय इन कंपनीयों के साथ एमओयू साईन हुए थे तब भी इसी तरह के बड़े निवेश और रोजगार का सपना देखा गया था लेकिन इस सपने का परिणाम आज यह है कि आज उद्योग विभाग का अपना करीब दो करोड़ रूपया इसमें डूब गया है। क्या 2006 और 2009 में साईन हुए इन एमओयू की जानकारी मुख्यमन्त्री और उद्योग मन्त्री को दी गयी है? यदि यह जानकारी मुख्यमन्त्री को है तो फिर यह जो निवेश सरकार का अपना डूब गया है उसकी भरपायी कैसे की जायेगी? भविष्य में निवेशकों के साथ इसी तरह का अनुभव न घटे इसको कैसे सुनिश्चित किया जायेगा। जिस तन्त्र के कारण इन कंपनीयों को वाच्छित क्लीयरैन्स नही मिल पाये हैं उसके खिलाफ क्या कारवाई की गयी है। औद्यौगिक निवेश से पहले सरकार को इन पक्षों पर गंभीरता से विचार करना होगा।

क्या हिमखण्ड में दबे जवानों की अहमियत पुलवामा में शिकार हुए जवानों से कम है

शिमला/शैल। 20 फरवरी को किन्नौर के पूह से आगे चीन सीमा पर सेना के पांच जवान हिमखण्ड के नीचे दब गये थे। इन जवानों को निकालने के लिये चलाये जा रहे राहत कार्य का जायज़ा लेने के लिये सरकार की ओर से मुख्यमन्त्री या उनका कोई भी मन्त्री मौके पर नही जा पाया है। इन जवानों में एक सोलन के नालागढ़ का भी है। जब इसके दबे होने की खबर परिवार तक पहुंची तब से परिवार का बुरा हाल है लेकिन परिवार की सुध लेने कोई नही पहुंचा। प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की संवेदनहीनता को हिलाने के लिये इस जवान के ही गांव के एक युवक ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ है इसमें रायफलमैन राजेश की मां की गुहार है।

वीडियो में ऋषि की मां मायादेवी कह रही है कि उसके बच्चे को फटाफट निकाला जाए। वह कह रही है कि इतनी ढील क्यों पाई गई है। उनके साथ कोई नहीं है। वीडियो में एक युवक कह रहा है कि गांव में कोई मीडिया वाला भी नहीं आ रहा है। हम आने जाने का खर्च देने को तैयार है। ये युवक सवाल भी उठा रहा है कि क्या मीडिया वाले तभी आते है जब कोई अमीर का बच्चा ऐसे बर्फ में दबा हो। ये युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगा रहा है कि ऋषि को तुरंत निकाला जाए।

ऋषि के चचेरे भाई धर्मवीर ने कहा कि वह वीडियो उन्होंने ही बनाया है। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। ऋषि की शादी अभी हाल ही में दिसंबर में हुई थी। उन्होंने कहा कि वीडियो में गांव की महिलाएं है व जो युवक कुछ कह रहा है वह भी गांव का ही है। धर्मवीर ने कहा कि ऋषि परिवार का एक ही कमाने वाला सदस्य है। दूसरा भाई मानसिक तौर पर कमजोर है। पूरा परिवार सदमे में है।

ऋषि की यूनिट से संपर्क कर रहे ऋषि के ताया रणदीप सिंह ने कहा कि सेना की ओर से उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। सचिवालय की ओर से कोई मिलने नहीं आया है न ही किसी मंत्री का फोन आया है। उन्होंने कहा कि बीते रोज उन्होंने एसडीएम नालागढ़ को फोन किया था कि हमारा बच्चा आठ दिन से गायब है। प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। ऐसे में अब एसडीएम नालागढ़ घर आए थे। इससे पहले पूर्व भाजपा के पूर्व विधायक के एल मेहता व कांग्रेस विधायक लखविंदर राणा भी एक दिन घर आाए थे।

उन्होंने कहा कि ऋषि के पिता चल फिर नहीं सकते। मां को पोलियो था जबकि उसका भाई इतना तेज नहीं है कि किसी स्तर पर बातचीत कर सके। उन्होंने कहा कि वह शादी के बाद 28 जनवरी को ही ड्यूटी पर वापस लौटा था। अब घर में सबका बुरा हाल है।

बचाव व राहत टीम को मिला मोबाईल– राहत व वचाव कार्य के बीते रोज आठवें दिन राहत व बचाव दल को मौके पर से एक मोबाईल मिला है। यह भी खोजी कुतों की मदद से मिला। इसके अलावा एक गैंती और टोपी मिली थी। आज जो मोबाईल मिला है वह बंद था जब उसे ऑन किया गया तो वह चल पड़ा। संभवत: वह यहां दबे रायफलमैन नीतिन राणा का है। लेकिन इस बावत कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो रही है। एडीएम पूह शिव मोहन सिंह सैणी ने कहा कि उन्हें इतनी ही जानकारी है कि एक मोबाईल मिला है। उन्होंने कहा कि अब भी राहत व बचाव कार्य दिन भर चलता रहा। मौसम खराब था लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि संभवत: कल कुछ सफलता मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौके पर 25 से 30 फुट ऊंची बर्फ है और नाला बेहद तंग है। इसके अलावा लगातार बर्फबारी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को 66 स्वर्ण पदक, 50 रजत पदक और 125 डिग्रियां की वितरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। उद्योग और तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह इस अवसर पर बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा छात्र जीवन जीता है और अपने जीवन में हमेशा नया सीखने की जिज्ञासा रखता है, वह सही मायनों राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों से कहा कि आपको डिग्रियां प्रदान की जा रही हैं, परन्तु यह अन्त नहीं है बल्कि ज्ञान, सृजनात्मकता तथा जीवन भर सीखने की इच्छा रखने की एक नई शुरूआत है।

दीक्षांत समारोह की प्राचीन परम्परा को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उपनिषदों में यह पहले से अकिंत है कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का एक भाग है, जहां पर शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अध्यापक छात्रों को समाज की उन्नति के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। दीक्षांत समारोह के समय जो दिशा-निर्देश दिए जाते थे, उनमें यह प्रमुख था कि छात्रों को ईमानदारी का बर्ताव करने के साथ-साथ अपने ज्ञान को जीवन भर लगातार बढ़ाना चाहिए तथा इसे समाज में भी बांटना चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे दिशा-निर्देशों और समृद्ध परम्पराओं का पालन करने के लिए यह उचित समय है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी डिग्रीधारक छात्रों से अपील की कि वे राष्ट्र की प्रतिबद्धता, करूणा और प्यार से सेवा करें तथा बिना किसी धन के लालच के आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें।

उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे ऐसे स्वप्न देखें जिनसे समाज को नई दिशा और समाधान मिल सकें। उन्होंने कहा कि अपनी शिक्षा और ज्ञान केवल अपने तक ही सीमित न रखें बल्कि इसका समाज को लाभ मिलना चाहिए तथा धर्म का भी यह सिद्धान्त है, जो सभी को प्रसन्नता की भावना प्रदान कर रहा है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को 66 स्वर्ण पदक, 50 रजत पदक और 125 डिग्रियां वितरित कीं।

उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं, ताकि राज्य के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े।

उन्होंने चिन्ता जताई कि आज भी समाज के कुछ वर्ग व्यवसायिक शिक्षा से वंचित हैं तथा हमें इनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं भी ऐसी मानवतापूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति को मदद पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने इस अवसर पर सभी मेधावी छात्रों एवं डिग्रीधारकों को बधाई दी तथा कहा कि उन्होंने अपने जीवन के प्रथम लक्ष्य को हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई की युवा विशेषकर तकनीकी शिक्षा से जुड़े युवा तकनीक प्रदान करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देंगे।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने राज्यपाल तथा मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और पहल का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 40 इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए और एमसीए कॉलेज कार्य कर रहे हैं तथा इनमें 18000 छात्र गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली और ऑड/ईवन सिमेस्टर परीक्षाएं जैसी सुविधाएं विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं।

राज्यपाल ने किया हमीरपुर जिले के कांगू में निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मानवता की सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं है और जीवन का उद्देश्य सबके साथ उदारता का व्यवहार होना चाहिए।

राज्यपाल जिला हमीरपुर के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कांगू में हिम मित्र सर्व कल्याण संस्थान द्वारा आयोजत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारम्भ करने के उपरान्त सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

हिम मित्र सर्व कल्याण संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभा मानवता की सेवा के लिए वर्षो से कार्य कर रही है तथा कांगू में पिछले कई वर्षो से निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजिन कर रही है, जहां पीजीआई चण्डीगढ़ व देश के अन्य भागों से आए चिकित्सक लोगों की सेवा कर रहे हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि जीवन में खुशी स्वस्थ शरीर पर निर्भर करती है, क्योंकि स्वास्थ्य ईश्वर द्वारा प्रदान की गई सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि केवल स्वस्थ व्यक्ति समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकता है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न बीमारियों का मुख्य कारण दूषित अनाज है। प्रत्येक व्यक्ति रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण बीमार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वस्थ अनाज प्रदान करने के लिए प्राकृतिक खेती अभियान आरम्भ किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश पूर्णतया प्राकृतिक खेती अपनाने वाला राज्य बन जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारी दिनचर्या में आए परिवर्तनों के कारण हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण भी इसका एक बड़ा कारण है।

इससे पूर्व राज्यपाल ने चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सकों को सम्मानित किया।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि हमीरपुर जिले के कांगू जैसे छोटे क्षेत्र में डाक्टरों की एक टीम लोगों के स्वास्थ्य जॉच कर रही है, जिसके लिए हिम मित्र लोक कल्याण संस्था बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि इस संस्था के माध्यम से मानवता के लिए किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं।

हिम मित्र सर्व कल्याण संस्था के अध्यक्ष विजय शर्मा ने क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए संगठन द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री क्षय रोग योजना के तहत क्षय रोग के 74 नये मामले आये सामने

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के तहत् क्षय रोग उन्मूलन के लिए चलाये गये अभियान की समीक्षा बैठक क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में आयोजित की गई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गुरूदर्शन गुप्ता ने जानकारी देते हुये बताया कि 13 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीवी मुक्त भारत-2005 की घोषणा की थी। क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए 10 से 24 मार्च तक जागरूकता पखवाड़ा मनाया जायेगा जिसमें सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस बात पर विशेष बल दिया गया कि क्षय रोगी व ठीक हो चुके क्षय रोगी खुल के सामने आएं व जागरूकता अभियान में अग्रणी भूमिका अदा करें।

इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि इस पखवाड़े में युवाओं के लिए रेड एरो पोस्टर प्रतियोगिता व वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश गुलेरी ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षय रोग योजना के अंतर्गत हर घर में जाकर रोगियों की पहचान की गई है तथा 74 नये मामले इस अभियान में पाये गये हैं। उन्होंने बताया कि क्षय रोगियों के घर जाकर पहचान कर उन्हें उपचार देना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला की 166 पंचायतों को संभावित चयनित किया गया है और इन पंचायतों के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा टीवी फोरम बनाया गया है, जिनकी बैठक आयोजित की जा रही है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनी इस फोरम के सदस्य, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, गांव के प्राईवेट डॉक्टर, स्कूल प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक व क्षय रोगी हैं।

डॉ. राजेश सूद ने बताया कि क्षय पोषण योजना के अंतर्गत क्षय रोगियों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह पोषण के लिए दिये जाते हैं। जिला में 3485 रोगियों को 54 लाख की राशि बैंक खातों में सीधी डाली गई है जोकि प्रदेश में सबसे अधिक है। उन्होंने सभी से आहवान् किया कि अन्य रोगियों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उनके बैंक खातों की जानकारी एकत्रित करके निक्षय सॉफ्टवेयर में अति शीघ्र डालें।

बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश गुलेरी, खंड चिकित्सा अधिकारी सहित क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम पर्यवेक्षक उपस्थित रहे व कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

13.50 करोड़ की लागत में बना हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने निर्माण भवन में 13.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण भवन के 'डी' खण्ड का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) के कर्मचारियों को काम करने के लिए बेहतर व्यवस्था प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए राज्य के लोगों को प्रदेश की सड़कों की दशा के बारे में ज्ञात होता है। राज्य की जलवायु स्थिति के कारण सड़कों की दशा खराब हो जाती हैं, इसलिए बेहतर सड़कों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्राधिकरण का गठन किया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भवन का नक्शा इस प्रकार बना होना चाहिए, जिससे दिन के प्रकाश का अधिकतम उपयोग हो सके। सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सड़कों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय निधि का अनुकूल उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने व्यवस्थित तरीके से निर्मित इस भवन पर प्रसन्नता व्यक्त की और इंजीनियरों से इस प्रणाली को अन्य परियोजनाओं में भी लागू करने का आग्रह किया।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 12.51 लाख रुपये का चौक मुख्यमंत्री को भेंट किया।

इस भवन का निर्माण 4033 वर्ग मीटर में किया गया है, जिसमे गुणवत्ता नियंत्रण विंग तथा इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना), लोक निर्माण का राष्ट्रीय उच्च मार्ग विंग, पुस्तकालय, राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं मकेनिकल, सामान्य शाखाएं, मटीरियल टेस्टिंग प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष व रिकार्ड कक्ष, जेई कक्ष, चालक कक्ष, ट्रांसफार्मर कक्ष, इलैक्ट्रिकल केन्द्र, हीटिंग कक्ष एवं अन्य स्टाफ के कमरे शामिल हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नन्दा ने कहा कि विभाग सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और समर्पण की भावना से कार्य करेगा।

159 समझौता ज्ञापनों से 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार: मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष जून माह के दौरान धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान पर्यटन, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं आयुष, विनिर्माण, फार्मासियूटिकल, अधोसंरचना

एवं लॉजीसिक्टस, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, एग्रो एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य वार्षिक सत्र 2018-19 तथा 'ट्रॉस्लेटिंग ऐस्पीरेशन इनटू रियल्टी' पर सत्र के दौरान सम्बोधित कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस इन्वेस्टर मीट के लिए सर्वांगीण सोच के साथ कार्य कर रही है ताकि निवेशक अपनी इच्छा से किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकें। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावना को प्रदर्शित करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि शिमला में विभिन्न कम्पनियों के साथ 159 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कुल 17,000 करोड़ का निवेश तथा 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की ओर एक बेहतर कदम है, जो कि प्रदेश सरकार की सक्रिय पहल का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि उद्यमियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीघ्र स्वीकृतियां मिल सकें। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, काला अम्ब, टाहलीवाल इत्यादि जैसे पहले से ही स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ अधोसंरचना सृजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सामने आने वाले सभी मामलों तथा समस्याओं को निपटाने के प्रयास भी किए जाएंगे।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को भारत के श्रेष्ठ निवेश गंतव्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार करने के अतिरिक्त सरकार उद्योगपतियों तथा सीआईआई जैसे संघों के सुझावों पर भी विचार करेगी। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी कि परिवहन संघों की अनैतिक हड़तालों के कारण औद्योगीकरण पर प्रभाव न पड़े।

सी.आई.आई के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष सचित जैन ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं तथा प्रदेश निवेश के लिए पंसदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने आशा जाताई कि हिमाचल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगी।

सी.आई.आई. के अध्यक्ष आई.एम. जी.एस सिद्धू ने उद्योग क्षेत्र में सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि परिवहन संघ औद्योगीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शहरी विकास विभाग द्वारा लगाए गए संपत्ति कर को सरल बनाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय मंत्री से रेल विस्तार मुद्दों पर चर्चा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की।

उन्होंने हिमाचल में रेल विस्तार के मुद्दे के अतिरिक्त मौजूदा रेल लाइनों के सुदृढ़ीकरण विषय पर उनसे विस्तार से चर्चा की।

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश में रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला- कालका रेल लाईन की गति बढ़ाने के अतिरिक्त नि:शुल्क वाई- फाई व बाबा भलकू संग्रहालय के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस रेल में राज्य की प्राकृतिक सुन्दरता का दृश्य पर्यटकों को देखने की सुविधा मुहैया करवाने के लिए विस्टा डोम डिब्बे लगाए जाएंगे।

राज्य खेल नीति में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल करने की मांग

शिमला/शैल। राज्य सरकार स्पेशल ओलंपिक भारत हिमाचल प्रदेश को खेल संघ का दर्जा देने व राज्य खेल नीति में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों को शामिल करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने निवास ओकओवर में उनसे मिलने आए स्पेशल ओलंपिक

में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कही।

प्रदेश के यह विशेष विद्यार्थी इस वर्ष 14 से 21 मार्च तक आबु धाबी में आयोजित होने वाले 15वें विश्व स्तरीय ग्रीष्म खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक हिमाचल प्रदेश ने मनाली तथा नारकण्डा में स्पेशल ओलंपिक भारत के लिए शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने राज्य कल्याण विभाग की ओर से सभी 7 विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये के चैक प्रदान किए। इन विशेष विद्यार्थियों में निशा, विनोद, अभिषेक, चिराग, शुभम, पूजा तथा रघुनाथ शामिल है। इसके अतिरिक्त जतिन सूद ने भी इस आयोजन में संयुक्त सहयोगी के रूप में भाग लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 91,958 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव बी. के अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम बच्चों को श्रेष्ठ शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

मुख्य सचिव अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष रूप से सक्षम बच्चों के ढली (शिमला)और सुन्दरनगर संस्थानों द्वारा मूक, बाधिर और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने कहा कि ढली स्थित संस्थान के छात्रों का चिकित्सा परीक्षण इन्दिरा गांधी मेडिकल शिमला में किया गया जिसमें विभिन्न बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया। सुन्दरनगर संस्थान के छात्रों का भी चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है तथा उन्हें भी आवश्यक यंत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रवण दोष से पीड़ित बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण (बैरा टेस्ट) को बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करने के लिए राज्य के जिला स्तरीय अस्पतालों में भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी श्रेणियों के 91,958 व्यक्तियों को अपंगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें से 11473 श्रवण दोष से पीड़ित हैं। विभाग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष रूप से सक्षमों के अपंगता को जॉचने व सूचीबद्ध करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगा, जिससे ऐसे व्यक्तियों की पहचान व उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसे युवाओं को विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त, सूजोप योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सकें।

अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के निदेशक हंसराज चौहान ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए इन संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने घर घर जाएं बूथ लेवल अधिकारी: उपायुक्त

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि जिला में बूथ लेवल अधिकारी अपने- अपने क्षेत्रों में घर- घर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से छूट गए पात्र युवाओं का पंजीकरण करेंगे। उन्होंने 1 जनवरी, 2019 तक चलने वाले इस अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं से 28 फरवरी से 3 मार्च तक सूचियों में अपना नाम दर्ज करवाने की अपील की है। उपायुक्त ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी संबन्धित मतदान केन्द्रों के परिवार रजिस्टर की भी जांच करेंगे और ऐसे नागरिकों की पहचान करेंगे जो नामांकित होने के लिए पात्र हैं, लेकिन तक अभी मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं। उपायुक्त ने बूथ लेवल अधिकारियों को संबंधित मतदान केन्द्र के तहत पंजीकरण से छूट गए पात्र युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए जागरूक करने पर विशेष प्रयास करने को कहा है। उन्होंने 'कोई मतदाता न छूटे' के संकल्प के साथ युवाओं, महिलाओं के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग लेकर सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई योग्य नागरिक अब भी अपनी वोट बनाने से वंचित रह गया हो तो वह अपने बूथ लेवल अधिकारी, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी एवं एसडीएम और जिला चुनाव कार्यालय में फार्म नंबर 6 भरकर वोट बनवा सकता है। वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी इसके बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी योग्य नागरिक मतदाता का नाम सूची में दर्ज होने से नहीं रहा है।

सड़क सुरक्षा विश्वभर में चिंता का विषय

शिमला/शैल। नवगठित राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की पहली बैठक परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

परिवहन मंत्री ने कहा कि परिषद का गठन राज्य में परिवहन और सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परिषद एक सलाहकार निकाय (एडवाईजरी बॉडी) है जो राज्य सरकार को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल राज्य केन्द्रित मुद्दा न होकर विश्वभर के लिए चिंता का विषय है तथा हिमाचल में कठिन भौगोलिक स्थितियां होने के कारण यहां बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ अधिक समन्वयपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

गोविंद सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिषद के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। उन्होंने अधिकारियों को जिला स्तरीय समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

अपमानित हो के जीने से अच्छा मरना है, मृत्यु तो बस एक क्षण का दुःख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुःख लाता है..... ''चाणक्य''

सम्पादकीय

अभिनन्दन की वापसी के बाद जवाब मांगते सवाल

विंग कमांडर अभिनन्दन वतन वापिस आ गये हैं यह एक सुखद समाचार है। यह वापसी कैसे संभव हुई और इसका श्रेय किसको कितना मिलना चाहिये? इस पर हो सकता है कि लम्बे समय तक बहस और होड़ चलती रही क्योंकि अभी तत्काल में सवाल चुनाव का है। इसलिये इस पक्ष पर अभी सवाल को आगे बढ़ाना मेरी नजर में ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण नही है। यहां ज्यादा प्रमुख सवाल दूसरे हैं क्योंकि जब अभिनन्दन की वापसी हो रही थी तब भी सीमापार से गोलीबारी के समाचार बराबर आ रहे थे। इस गोलीबारी में हमारे जवानों के शहीद होने के समाचार बराबर आ रहे थे और यह सब कुछ चल ही रहा है। इस की न्यूज चैनलों में जिस ढ़ग से रिर्पोटिंग आ रही है उससे यही संकेत उभरे हैं कि युद्ध अवश्यंभावी है क्योंकि यह रिर्पोटिंग न्यूज एंकरों से ज्यादा उनके सेना और सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता होने का अहसास करवा रहे हैं। सरकार इस रिर्पोटिंग पर खामोश चल रही है और खामोशी से इस अवधारणा को ही बल मिल रहा है। इस परिदृश्य में अब तक घटे पूरे घटनाक्रम पर फिर से नजर डालने की आवश्यकता हो जाती है।

घटनाक्रम के अनुसार पहले पुलवामा घटता है। इस आतंकी हमले में सी आर पी एफ के चालीस से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। जब इन जवानों के शव इनके पैतृक स्थानों पर पहुंचते हैं उस पर पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। देश के हर राज्य में लोग सड़कों पर कैण्डल मार्च पर उतर आते हैं। पाकिस्तान से कड़ा बदला लेने की मांग उठती है क्योंकि आम आदमी को यह बताया जाता है कि इस आंतकी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस जनाक्रोश के बाद सरकार सेना को इससे निपटने के लिये खुला हाथ दे देती है और सेना एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राईक करके आंतकियों के ठिकानों पर तेरह दिन बाद कारवाई करती है। न्यूज चैनलों के मुताबिक इस कारवाई में 150 से 350 तक आतंकी मारे जाते हैं। वैसे अधिकारिक तौर पर कहीं से कोई आंकडा जारी नही हुआ है। इस सर्जिकल स्ट्राईक को बड़ी कारवाई करार दिया जाता है। यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ यह एक बड़ी कारवाई है। पाकिस्तान की एसैंम्बली में इसकी चर्चा उठती है और हमारे चैनल इस कारवाई को देश के लोगों के सामने परोसते हैं। पाकिस्तान एसैंम्बली में इमरान खान सरकार की निन्दा की जाती है और इस निन्दा का परिणाम होता है कि पाकिस्तान अपने जन दबाव में आकर बदले में सैनिक कारवाई कर देता है। इस कारवाई में पाकिस्तान का एक विमान नष्ट हो जाता है। हमारा भी एक विमान क्रैश हो जाता है। हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता है। पाकिस्तान तुरन्त इस पायलट के उनके कब्जे मे होने की जानकारी सार्वजनिक कर देता है। यह जानकारी सार्वजनिक होते ही हमारी प्राथमिकता इस पायलट की सुरक्षा और इसकी घर वापसी हो जाती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान का एक वकील इस पायलट पर पाकिस्तान में मुकद्दमा चलाने की मांग की एक याचिका दायर कर देता है। उच्च न्यायालय इस याचिका को रद्द करते हुये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के फैसले को बहाल रखता है और अभिनन्दन की वापसी हो जाती है।

लेकिन इस वापसी के बाद भी घटनाएं जारी हैं इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह स्पष्ट हो पायें कि हमारी समस्या पाकिस्तान है या आतंकवाद। यदि समस्या पाकिस्तान है तो उस समस्या से निपटने के लिये क्या सैनिक कारवाई के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प है। इसके लिये तुरन्त एक सारे राजनैतिक दलों की बैठक बुलाकर उसमें यह फैसला लिया जाना चाहिये। यदि यह आम राय बनती है कि पाकिस्तान ही मूल समस्या है और युद्ध ही उसका एक मात्र हल है तो तुरन्त प्रभाव से एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करके जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो एक फैसला लिया जाना चाहिये क्योंकि देश इसका स्थायी हल चाहता है। यदि समस्या आतंकवाद है तो उसके लिये घर के भीतर ही निपटना होगा जिस तरह से पंजाब और बंगाल में निपटा गया था। उसके लिये हमारी नीयत और नीति दोनो साफ होनी चाहिये। इस आतंकवाद से निपटने के नाम पर यह नही होना चाहिये कि हर मुसलमान आतंकी है। हर वह व्यक्ति जो हमारी विचारधारा से मेल नही खाता वह देश द्रोही है। आज उस देश में करीब पच्चीस करोड़ मुसलमान हैं जो वैसे ही नागरिक हैं जैसे हिन्दू और अन्य है। इतनी बड़ी मुस्लिम जनसंख्या के कारण ही आज हम इस्लामिक देशों के सम्मेलन में शामिल हो पाये हैं और जब हम इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं तो इस अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह हमारी जिम्मेदारी और जबावदेही बन जाती है कि हमारे मुस्लिम नागरिकों की ओर से उन पर किसी तरह के भेदभाव करने के आरोप हमारी सरकार पर न लगें। भेदभाव का आरोप सरकार के साथ हमारे राजनीतिक दलों पर भी नही लगना चाहिये। परन्तु आज यह दुर्भाग्य है कि सतारूढ़ दल भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनावों में एक भी मुस्लिम को टिकट देकर चुनाव नही लड़वाया। बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद विधान सभा चुनावों में भी ऐसा ही हुआ है। आज भाजपा सरकार में जो भी मुस्लिम चेहरे हैं वह सब मनोनित होकर आये हैं चयनित होकर नही। बल्कि सरकार बनने के बाद लव जिहाद और गौ रक्षा जैसे जितने भी मुद्दे सामने आयें हैं उनमें मुस्लिम एक पीड़ित वर्ग के रूप में ही सामने आया है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ है इसका कोई संतोषजनक जवाब सामने नही आया है। इन्ही कारणों से आज भाजपा की छवि एक मुस्लिम विरोधी दल का रूप ले चुकी है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसलिये आज जहां देश इस रोज-रोज की आतंकी समस्या के स्थायी हल की मांग कर रहा है वहीं पर सरकार की स्थिति बहुत कठिन होती जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर आज सरकार चुनाव की पूर्व संध्या पर कारवाई की बात कर रही है जबकि इस पर एक विस्तृत बहस की आवश्यकता है जिसके लिये आज समय नही है। इसी तरह कुछ और सवाल हैं जिनपर सरकार की ओर से जबाव नही आया है। गुजरात दंगों को लेकर 28 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय में आयी रिपोर्ट में कुछ मामलों में पुलिस को स्पष्ट दोषी ठहराया गया है लेकिन कोई कारवाई सामने नही आई है। राणा अयूब की ''गुजरात फाईल्ज'' पर भी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। यही नही अभी पुलवामा के बाद एक न्यूज साईट में हाफिज सईद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मिलाते हुए एक फोटो दिखाया गया है और दावा किया गया है कि यह फोटो आजम खान ने जारी किया है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। इसी तरह अब अभिनन्दन की वापसी के बाद यू टयूब में एक आडियो एवी डांडिया के हवाले से जारी किया गया है। यह सब कुछ सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन इस पर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया जारी नही की गयी है। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समय सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आना आवश्यक हैअन्यथा इस सबके परिणाम घातक होंगे।

पाकिस्तान को पानी रोकने वाला बयान कितना सही कितना झूठ

गौतम चौधरी

पुलवामा फिदायीन आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से माहौल तैयार हुआ है। मसलन पूरा देश आक्रोशित है। देश के लगभग हर कोने से यह आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाई जाए। हालांकि पाकिस्तान बार-बार कह रहा है कि इस घटना के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है लेकिन पाकिस्तान की नीति आतंकवाद के संपोषण की रही है। ऐसे में इस हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर उंगली उठना स्वभाविक है। फिर पाकिस्तान में पनाह लिए अजहर मसूद के आतंकवादी संगठन जैश-ए- मुहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान चाहे जो भी कहे लेकिन इस हमले में मुकम्मल तौर पर प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से तो उसका हाथ जरूर है। यदि सचुमच पाकिस्तान के दावे सही हैं तो जैसे ही जैश ने इस घटना की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उलट जैश सरगना अजहर मसूद की सुरक्षा बढ़ा दी गयी।

खैर, किसी दुश्मन देश से अच्छे व्यवहार की कल्पना कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान चाहे जो भी कह ले लेकिन वह अपने निर्माण काल से ही भारत विरोधी है। यदि हम ऐसा कहे कि भारत विरोध उसकी विदेश नीति का हिस्सा है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। हमारे एक खास मित्र जो पाकिस्तान आते जाते रहते हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लाम की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए हुआ है। मलतब साफ है कि इस्लाम पाकिस्तान की विदेश नीति का भी हिस्सा है। ऐसे में भारतीय जीवन मूल्य पर आक्रमण पाकिस्तान की नियति है और पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है। तो साफ है कि भारत, पाकिस्तान से कुछ भी सकारात्मक अपेक्षा नहीं रख सकता है। हालांकि आज भी कुछ लोग भारत- पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों की वकालत करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक भारत के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं।

तो पाकिस्तान, भारत का घोषित रूप से दुश्मन है। वह अपनी हड़कर से बाज नहीं आएगा। जनरल जियाउल हक के समय पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्षद्मयुद्ध की रणनीति बनाई थी। पाकिस्तान की वर्तमान विदेश नीति उसी रणनीति का हिस्सा है। उसी नीति के तहत कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को पाकिस्तान सहयोग कर रहा है। अब भारत को इस समस्या से निवटने के लिए क्या करना चाहिए उसपर भारत का दृष्टिकोण सदा से भ्रम पैदा करने वाला रहा है लेकिन जब से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है तबसे और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है। कश्मीर पर सरकार की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार की ओर से नए-नए ब्यान और भ्रम पैदा करने लगा है। मसलन विगत दिनों हमारी सरकार के एक खास केन्द्रीय मंत्री द्वारा पाकिस्तान को पानी रोकने की बात कही गयी। दरअसल, जो ब्यान दिए गए उसकी पड़ताल होनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। सचमुच हमारी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रही है कि केवल डपोरसंखी ब्यानबाजी कर रही है।

23 फरवरी के एक दैनिक हिन्दी अखबर के 16वें पन्ने पर एक खबर छपी। खबर एजेंसी की थी। खबर में साफ-साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान को पानी रोकने वाला निर्णय नया नहीं है। यह निर्णय पुराना है लेकिन हमारे पास फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए हम पानी नहीं रोक पा रहे हैं। यह खबर जल संसाधन मंत्रालय के मीडिया एवं संचार महानिदेशक नीता प्रसाद के हवाले आयी है। प्रसाद का कहना है कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गड़करी वही दुहरा रहे हैं जो विगत कई सरकारें दुहराती रही है। मसलन इसमें कुछ भी नया नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक, सिंधु जल समझौते के तहत रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का औसतन 33 मिलियन एकड़ फीट पानी भारत के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। भारत सरकार ने सतलुज पर भाखड़ा बांध, ब्यास पर पोंग व पांदोह बांध एवं रावी पर थेन यानी रंजीतसागर बांध का निर्माण किया है। इसके अलावा ब्यास- सतलुज लिंक, माधोपुर-व्यास लिंक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इत्यादि से भारत पूर्वी नदियों के करीब 95 प्रतिशत पानी का उपयोग खुद के लिए करता है। इसमें केवल रावी नदी का पानी पाकिस्तान को जाता है। यह पानी माधोपुर के रास्ते पाकिस्तान में चला जाता है।

एक अनुमान में बताया गया है कि मात्र दो एमएफए पानी पाकिस्तान जाता है। इसके लिए भारत सरकार के पास अभी तक कोई प्रबंधन नहीं है, इसलिए यह पानी पाकिस्तान को चला जाता है। ऐसे में केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी का ब्यान बेहद हल्का और जनता को गुमराह करने वाला ब्यान है। हालांकि केन्द्र सरकार इस पानी को रोकने और और उसे अपने उपयोग में लाने का प्रयास कर रही है। इस पानी के द्वारा पंजाब और जम्मू-कश्मीर की लगभग 37 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकती है और कम से कम 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो भारत के हिस्से का केवल पांच प्रतिशत पानी ही पाकिस्तान को जाता है, वह भी प्रबंधन की कमी के कारण। शायद यही करण है कि विगत दिनों जब गड़करी ने पानी रोकने वाला ब्यान जारी किया तो पाकिस्तान ने साफ-साफ कह दिया कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

दूसरी ओर सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, चेनाव और झेलम नदी का पानी पाकिस्तान को मिलना तय किया गया था। चूंकि उन दिनों भारत की अधिकतर भूमि पानी विहीन थी इसलिए समझौते के तहत सिंधु नदी के कुल पानी का 20 प्रतिशत हिस्सा भारत को दिया गया। जानकारों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ पानी पर पंगा लेगा तो पाकिस्तान विश्व जल पंचाट में भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देगा और अभी जो भारत को सिंधु नदी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पानी मिल रहा है उस पर वह अड़ंगा खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि सिंधु नदी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पानी भी भारत उपयोग नहीं कर पा रहा है लेकिन उस पानी के बारे में हमारे राजनेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए यह कहना कि भारत जब अपने हिस्से का पानी रोक लेगा तो पाकिस्तान पानी-पानी के तरस जाएगा यह भ्रम पैदा करने और अपनी जनता को गुमराह करने वाले ब्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे राजनेता को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ठोस इंतजाम करना चाहिए। दूसरी ओर हमें अपने आंतरिक अंतरविरोधों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जो इस सरकार में बढ़ी है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो दुश्मन देश अपनी योजना में कामयाब हो जाएंगे। यदि अंतरिक अंतरविरोध इसी तरह बढ़ता रहा तो दुश्मन देश अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ाने में भी सफल होंगे।

प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अनेकों कदम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरित क्षेत्र बढ़ाने व वन संपदा के संरक्षण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए है और वन संपदा के संरक्षण व वनों के विकास के लिए आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित क्षेत्र को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और वन विभाग द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के विशेष पौधारोपण अभियान आरंभ किया गया है। इसी उद्देदश्य के मद्देनजर राज्य में 106 स्थानों पर तीन दिवसीय पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान 7,493 हैक्टेयर क्षेत्र में 67,05,982 पौधे प्रदेश के विभिन्न भागों में रोपित किए गए। इस अभियान में प्रदेशभर के 86,251 लोगों ने भाग लिया तथा 17,63,899 पौधे रोपित किए गए जिनमें से 8,09,299 पौधे चौड़े पत्ती प्रजातियों के थे।

वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि वनों में आग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश में पहली बार वन अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया तथा लोगों को नुक्कड़ नाटक गीत प्रतिस्पर्धा द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए जागरूक किया गया। आग पर नियंत्रण पाने के लिए 13 हजार स्वयं सेवकों की 'रेपिड फोरेस्ट फायर फाईटिंग फोर्स' का गठन किया गया ताकि वनों में आग लगने की सूचना का तुरन्त पता लग सके और उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसके अतिरिक्त लोगों को वन अग्नि से बचाने के लिए जागरूक करने बारे व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया। प्रदेश के वन अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों को दो वन फाइटिंग वाहन उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश सरकार ने फील्ड कर्मचारियों को आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा उनका मनोबल बढ़ाने व सुरक्षा हेतु वन रक्षकों को हथियार उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना आरंभ की है जिसके तहत वन रक्षकों को उचित हथियार खरीदने के लिए 12 हजार रुपये प्रति वन रक्षक उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। वन रक्षकों को सुरक्षा यंत्र जैसे फायर प्रूफ जैकेट, दस्ताने, बूट इत्यादि भी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वे वन अग्नि से प्रवाही ढंग से निपट सके।

प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित बनाने के लिए सामुदायिक वन संवर्धन योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत खाली भूमि को ग्रामीणों को पौधरोपण के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत पौधरोपण उद्देदश्य से स्कूलों को साथ लगती खाली वन भूमि का आवंटन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देदश्य विद्यार्थियों में वन एवं पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करना है।

जंगली जड़ी बूटियों के विपणन तथा निजी भूमि पर इनके उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 'वन समृद्धि जन समृद्धि' योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत जंगली जड़ी बूटियों के विपणन व रखरखाव के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस योजना में जड़ी बूटियों पर आधारित

औषधि निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत तक का अनुदान देने तथा व्यक्तिगत निजी उद्यमियों को भी जड़ीबूटी व्यापार सम्बन्धित प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों को उठाने की योजना के अंतर्गत पाईन निडल आधारित उद्योग लगाने के लिए पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सर्वोत्तम वन प्रबंधन समिति पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री वन मित्र पंचायत पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत वन संरक्षण/अग्नि संरक्षण, बेहतर पौधरोपण को बढ़ावा देने, जैव विविधता संरक्षण व अन्य अग्नि सम्बन्धित गतिविधियों की रोक के लिए मैकेनिजम विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से 50 हजार रुपये तक के पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष विश्व वाणिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

आजीविका से जोड़कर वन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिका द्वारा वित्त पोषित 800 करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश वन ईको प्रणाली प्रबंधन एवं आजीविका स्तरोन्यन परियोजना प्रदेश के 6 जिलों कुल्लू, मण्डी, लाहौल-स्पीति, शिमला, बिलासपुर तथा किनौर में आरंभ की गई है। इस परियोजना के तहत वन तथा पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 460 वन समितियां गठित की गई है। एक संयुक्त वन प्रबंधन तथा लोक वन प्रबंधन समिति भी वन विभाग द्वारा गठित की गई है।

भारतीय वन सर्वेक्षण 2017 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 393 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा प्रदेश हित में समय-समय में पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों के परिणामस्वरूप यह सब संभव हो सका है और आज हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल जहां वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है।

समय है देश विरोधियो के चहरे से नकाब उतारने का

अगर 370 और 35A संविधान से हटाना नामुमकिन है तो संविधान में संशोधन करके एक और धारा जोड़ना तो मुमकिन है? तो एक नई धारा जोड़ी जाए कि हर भारतीय की तरह कश्मीर के लिए भी भारत के संविधान ध्वज सेना और संप्रभुता का सम्मान और रक्षा सर्वोपरि होगी और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि दंडनीय अपराध होगी। चूंकि कश्मीर भारत का ही अंग है इसलिए कश्मीर का ध्वज अकेले नहीं हमेशा भारत के ध्वज के साथ ही फहराया जाएगा।

''डॉ. नीलम महेंद्र''

पुलवामा की आतंकवादी घटना के बाद से जिस प्रकार के कदम हमारी सरकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है उससे ना सिर्फ देश में एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ है बल्कि इन ठोस कदमों ने हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को भी ऊंचा किया है। लेकिन यह खेद का विषय है कि सरकार के जिन प्रयासों का स्वागत पूरा देश कर रहा है उनका विरोध देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के स्थानीय विपक्षी दल कर रहे हैं। काश कि ये समझ पाते कि इनका गैर जिम्मेदाराना और सरकार विरोधी आचरण देश विरोध की सीमा तक जा पहुंचा है । क्योंकि अपने राजनैतिक हितों के चलते इन लोगों ने कश्मीर समस्या को और उलझाने का ही काम किया है।

पाक परस्ती के चलते जो लोग यह कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का विकल्प नहीं होता उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का पहला विकल्प नहीं होता लेकिन अंतिम उपाय और एकमात्र समाधान अवश्य होता है। श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान देकर महाभारत के युद्ध को धर्म सम्मत बताया था। और जो लोग यह कहते हैं कि 1947 से लेकर आजतक कश्मीर के कारण भारत और पाकिस्तान में कई युद्ध हो चुके हैं तो क्या हुआ? तो उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि हर युद्ध में हमारी सैन्य विजय हुई लेकिन राजनैतिक हार। हर युद्ध में हम अपनी सैन्य क्षमता के बल पर किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब होते थे लेकिन हमारे राजनैतिक नेतृत्व हमें किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं पाए। यह वाकई में शर्म की बात है कि हर बार हमारी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त देने के बावजूद हमारी सरकारें कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल पाई। हर बार दुश्मन से सैन्य मोर्चे पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद भी हम राजनैतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर विफल रहे, 1948 में जब हमारी सेनाएँ पाक फौज को लगातार पीछे खदेड़ने में कामयाब होती जा रही थी तो कश्मीर मामले को संयुक्तराष्ट्र क्यों ले जाया गया? क्यों 1965 में हमें भारतीय सेना द्वारा पाक का जीता हुआ भू

भाग वापस करना पड़ा। 1971 में जब पाक ने अपनी पराजय स्वीकार करी थी और भारतीय सेना के समक्ष 90000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था तब संपूर्ण कश्मीर लेकर उसका स्थाई समाधान ना करके शिमला समझौता क्यों किया गया?

इसे राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव कहा जाए या मजबूरी? कारण जो भी रहा हो लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि हमारे द्वारा इतिहास में की गई कुछ गलतियों की सजा पूरा देश आजतक भुगत रहा है खासतौर पर हमारी सेनाएँ और उनके परिवार। पहले जो पाकिस्तान आमने सामने से युद्ध करता था, अब आतंकवादियों के सहारे छिप कर वार करता है।

लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व इस मुद्दे पर आरपार की निर्णायक लड़ाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति जता चुका है जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। लेकिन इसे क्या कहा जाए कि आज जब देश की हर जुबाँ पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात है तो महबूबा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं। जब घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो वो विरोध करती हैं। 35A और 370 की बात आती है तो विरोध करती हैं। दरसअल इस प्रकार के नेता और उनके राजनैतिक स्वार्थ ही कश्मीर की समस्या के मूल में हैं। जब हमारे सैनिक इनकी रक्षा में शहीद होते हैं तब ये लोग आतंकवादियों से हथियार छोड़ कर बात करने के लिए क्यों नहीं कहते इसके विपरीत जब हमारी सेना कार्यवाही करने लगती है तो ये बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की बात करते हैं। जब हमारी सेनाओं पर पत्थरबाजी होती है तो इन्हें पत्थरबाज भटके हुए बच्चे लगते हैं लेकिन जब अपने बचाव में इन पत्थरबाजों पर सेना कोई भी कार्यवाही करती है तो वो इन्हें सेना का अत्याचार दिखाई देता है। आखिर क्यों हमारे निहत्ते सैनिकों पर हमला करने वाले अब्दुल डार में इन्हें एक आतंकवादी नहीं एक भटका हुआ कश्मीरी दिखाई देता है। भले ही घाटी से पंडितों को खदेड़ दिया गया हो और विरोध में इन्होंने एक शब्द ना बोला हो क्योंकि कश्मीर पर सिर्फ कुछ विशेष कौमों का अधिकार है लेकिन इनका पूरे देश पर अधिकार है। इनका अधिकार है कि भारत सरकार इनकी सुरक्षा करे लेकिन ये भारत की सुरक्षा में कोई योगदान नहीं देंगे। इनका अधिकार है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आए तो भारत सरकार इनकी मदद करे लेकिन जब भारत पर आपदा आए तो इनका कोई दायित्व नहीं। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के पृथक संविधान और ध्वज का सम्मान करें लेकिन भारत के संविधान और ध्वज का अपमान कश्मीर में हो सकता है। यह इनका अधिकार है कि भारत सरकार कश्मीर की संप्रभुता की रक्षा करे लेकिन भारत की संप्रभुता से इन्हें कोई लेना देना नहीं। यह इनका अधिकार है कि एक कश्मीरी भारत में कही भी रह सकता है भारत सरकार उसकी सुरक्षा करे लेकिन पूरे देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक खुद भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि इनका मानना है कि इनकी सुरक्षा में सुरक्षा बलों का शहीद हो जाना उनका फर्ज है और भारत सरकार से अपने लिए सहायता और सुरक्षा लेना इनका अधिकार है। लेकिन जिस सरकार से ये अपने लिए अधिकार मांगते हैं क्या उसके प्रति इनका कोई दायित्व नहीं है? जिस सेना से ये बलिदान मांगते हैं क्या उनके प्रति इनके कोई फर्ज नहीं है?

इसलिए जरूरत है समय की नजाकत को समझा जाए। देशविरोधियों के चेहरों पर से नकाब हटाए जाएं। अगर 370 और 35A संविधान से हटाना नामुमकिन है तो संविधान में संशोधन करके एक और धारा जोड़ना तो मुमकिन है? तो एक नई धारा जोड़ी जाए कि हर भारतीय की तरह कश्मीर के लिए भी भारत के संविधान ध्वज सेना और संप्रभुता का सम्मान और रक्षा सर्वोपरि होगी और भारत की अखंडता के खिलाफ किसी प्रकार की गतिविधि दंडनीय अपराध होगी। चूंकि कश्मीर भारत का ही अंग है इसलिए कश्मीर का ध्वज अकेले नहीं हमेशा भारत के ध्वज के साथ ही फहराया जाएगा।

सिराज दीप उत्सव, थुनाग को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने को स्वीकृति

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में सेवाकाल के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को करूणामूल्क आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए नीति को सरल बनाने का निर्णय लिया गया ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की।

नई नीति के अनुसार, कर्मचारी की 50 वर्ष तक की आयु सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया गया है और अब मृतक कर्मचारी की सेवानिवृति आयु को करूणामूल्क आधार पर रोजगार देने के लिए आयु सीमा माना जाएगा। साथ ही आय सीमा के मानदण्ड को भी दो लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की नाहन तहसील के मौजा खेरी में उद्योग विभाग की 16-11 बीघा भूमि ईएसआईसी के महा निदेशक को 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की स्थापना के लिए 95 वर्ष के पट्टे पर एक रुपये प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य की हाइड्रो पॉवर नीति में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि इसे 5 मेगा वॉट से कम परियोजनाओं वाले स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के लिए और आकर्षक बनाया जा सके।

पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 आंतकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा जिले के शहीद तिलक राज के सम्मान में मंत्रिमण्डल ने उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी को उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति देने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में चार पटवार सर्कल सृजित करने को मंजूरी प्रदान की हैं। ये पटवार सर्कल शिमला जिला की उप-तहसील देहा के टिक्कर, हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र के बटारन, मण्डी जिला की थुनाग तहसील के अन्तर्गत गुडाह और डेहर उप-तहसील के अन्तर्गत खुराहल में सृजित होंगे। इन पटवार सर्कलों के लिए पटवारी के चार पद सृजित कर इन्हें भरने का भी निर्णय लिया गया है।

बैठक में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अन्तर्गत गठित हि.प्र. राज्य शिक्षा सोसायटी के तकनीकी स्टाफ को अनुबंध आधार पर राज्य लोक निर्माण और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विल्य करने का निर्णय लिया गया।

शिमला जिला के ननखड़ी में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने के साथ तहसील कल्याण कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है।

बैठक में शिमला के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामपुर में बिस्तरों की क्षमता 10 से बढ़ाकर 20 करने को मंजूरी दी गई। इसी प्रकार, मण्डी जिला के जोगेन्दरनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी बिस्तरों की क्षमता 10 से बढ़ाकर 30 करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में खोलानल पंचायत के शराटी गांव और काओ पंचायत के बकाहरी गांव तथा कांगड़ा जिला की मकदोली पंचायत के मकदोली गांव और कोहलापुर पंचायत के हन्दल गांव में नियमित पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति दी है। इन पशु औषधालयों के लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया।

मण्डी जिला की सरकाघाट तहसील के ठौणा में पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर आवश्यक स्टाफ के सृजन के साथ पशु चिकित्सालय बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कांगड़ा जिला के पशु चिकित्सालय कोटला बेहर को बेटरीनेरी पॉलीक्लिनिक के रूप में स्तरोन्नत करने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें

भरने का निर्णय लिया गया है।

कुल्लू जिला के बंजार में पुलिस उप-मण्डल (एसडीपीओ) कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए छः पदों को सृजित कर भरा जाएगा।

कांगड़ा जिला के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र में नया पॉलीटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 80 पदों के सृजन के बाद भरा जाएगा।

बैठक में कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां नागरिक अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 करने और विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उन उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने लिपिक के पदों के लिए एलडीआर के अंतर्गत आयोजित लिखिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है।

पंचायत चौकीदारों का वेतन 1 अप्रैल, 2019 से 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सिराज दीप उत्सव, थुनाग को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान की।

किनौर जिला के सागंला और भावानगर में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद सृजित करने और इन्हें भरने के साथ अग्निश्मन चौकियां खोलने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के भवारना पुलिस थाने के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी।

सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाणाघाट और जड़ोल-टपरौली तथा शिमला जिला के घूंड में विज्ञान की कक्षा आरंभ करने व आवश्यक पदों के सृजन व इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान की जिसमें वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में नवीनीकरण के बाद ठेको के आवंटन को स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों को शराब की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शराब भट्टीयों को प्रोत्साहित करने के लिए शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने शराब पर परचून मूल्य से अतिरिक्त मूल्य या कम मूल्य लेने और बार में नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में टोल की नीलामी को नीलामी एवं टैंडर आधार पर करने पर भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एनपीए के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित हागे।

हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन कर भरा जाएगा।

प्रदेश में 'स्किल स्ट्रैंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में पीजीटी के पद को प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया गया।

कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मण्डी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेड़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु-1 तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

महिलाओं के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार वचनबद्धः डॉ. सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं

के कल्याण की कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। डॉ. सैजल सोलन जिला के विकास खण्ड कण्डाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्वारग के गांव देहूं में 4.50 लाख रूपये की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन की आधारशिला रखने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष के दौरान ऐसी सभी विधवाएं, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है के लिए हिमकेयर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत, बिना कोई प्रीमियम दिए 5 लाख रुपये तक का स्वस्थ बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परित्यक्त महिलाओं/विधवाओं को दो बच्चों के पालन-पोषण हेतु प्रति बच्चा, प्रति वर्ष सहायता राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया गया है। इसके उपरान्त जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही है।

डॉ. सैजल ने कहा कि सोलन ज़िले में वर्तमान में 1281 आंगनबाडी केन्द्रों में कुल 36 हजार 865 बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को पोषाहार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढाओ के अन्तर्गत सोलन ज़िला के लिए 50 लाख रूपये की कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में सोलन ज़िले में 71 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर पर एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत पौधा भी रोपित किया। उनहोंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कुमारी ललिता, कुमारी समायरा तथा कुमारी सैजल को सम्मानित किया। डॉ. सैजल ने क्षेत्र के 11 महिला मंडलों को उत्कृष्ट कार्य के लिए 1.52 लाख रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्य खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम गुलेरिया, सोलन भाजपा मंडल अध्यक्ष रविन्द्र परिहार तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

ग्राम पंचायत क्वारग के उप प्रधान ज्ञान ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा उन्हें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया।

निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का कोर्स 25 मार्च से होगा शुरू

धर्मशाला/शैल। पीएनबी आरसेटी के निदेशक कमल प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब नैशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, धर्मशाला बेरोजगार युवक व युवतियों को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण कोर्स 25 मार्च से आरंभ करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां भाग ले सकती हैं। जिन्हें स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें बैंक से ऋण भी उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह संस्थान जिला कांगड़ा में 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करवाता है। कमल प्रकाश ने बताया कि संस्थान द्वारा आने वाले दिनों में प्लंबिंग का काम 30 दिन, घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी 30 दिन, मोबाईल रिपेयरिंग 30 दिन तथा ड्रैस डिजाईनिंग 30 दिन के कोर्स निःशुल्क शुरू किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवक-युवतियां डीआरडीए भवन में स्थित उनके संस्थान में व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके मोबाइल नम्बर 94183-36850 तथा कार्यालय दूरभाष नम्बर 8280592105 व 01892-227122 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किये जाएंगे जिसके माध्यम से प्रशिक्षणार्थी स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए संस्थान के माध्यम से कांगड़ा जिला के किसी भी बैंक से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 21443 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 28 फरवरी, 2019 तक ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 31914 मूल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21443 का निपटारा किया जा चुका है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 752 अवमानना याचिकाओं, 34 समीक्षा याचिकाओं, 109 निष्पादन याचिकाएं और 8738 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6481 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 1638 मामलों का निपटारा किया गया है।

जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से राष्ट्र के लिए उड़ान-2 का शुभारंभ

शिमला/शैल। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से शिमला से चण्डीगढ़ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हेलिकॉप्टर उड़ान को हरी झण्डी दिखाकर राष्ट्र के लिए उड़ान-2 योजना का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर नई दिल्ली से

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को सम्बोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि उड़ान-2 योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीमारी तथा अन्य आपात स्थिति के समय बेहतर हवाई सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ आम लोगों को भी सुविधाजनक व आरामदायक सुविधाएं प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि आज का दिन राज्य के विकास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के तीव्र विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा उड़ान-2 प्रदेश के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में वरदान सिद्ध होगी तथा इस सुविधा से प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा देश के लिए उड़ान-2 योजना का हिमाचल में शुभारंभ करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 63 हवाई हेलीपेड विद्यमान हैं तथा शिमला व मण्डी जिला के कंगनीधार में हेलीपेड हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ओ.एल.एस सर्वेक्षण किया गया रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उड़ान-2 के तहत चण्डीगढ़ से प्रात: 10 बजे उड़ान रवाना होगी और 10:30 बजे शिमला पहुंचेगी तथा शिमला से 10:55 पर रवाना होकर 11:25 पर चण्डीगढ़ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आरम्भ में सप्ताह में तीन दिन यह उड़ान होगी तथा दो सप्ताह पश्चात सप्ताह में छ: उड़ाने होंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ का किराया 2880 रुपये होगा ताकि आम लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला-चण्डीगढ़ के अतिरिक्त उड़ान-2 योजना के तहत शिमला-कुल्लू और शिमला-धर्मशाला के लिए भी ऐसी सुविधा आरम्भ की जाएगी, जिससे राज्य में सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई सम्पर्क सेवाएं सुनिश्चित हो सकेगी। इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, परन्तु राज्य की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को राज्य में हवाई सम्पर्क को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभाग सिंह ने कहा कि उड़ान-2 के अंतर्गत पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सप्ताह में शिमला से चण्डीगढ़ छ: दिन हेलिकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएगी।

केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' योजना शुरू

शिमला/शैल। अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित क्षेत्र के तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपए प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' योजना शुरू की गई है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत श्रमिकों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों, मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड-डे-मील वर्कर आदि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

राघव शर्मा ने बताया कि योजना से जुड़ने के लिए श्रमिकों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड और बैंक खाते की कापी साथ लाना होगी। अधिक जानकारी के लिए केंद्र व राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों और एलआईसी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए प्रति माह तथा आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। अंशधारकों से ली जाने वाली राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। यह 'परिवार पेंशन' होगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

विंग कमांडर की रिहाई पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को दी बधाई

शिमला/शैल। प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान से वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह भारत की एक बड़ी जीत है।

मंत्रिमंडल ने इस कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है जिसके कारण पाकिस्मान को विंग कमांडर को केवल दो दिनों के भीतर ही रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा।

नए उभरते भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकास मॉडल पर सम्मेलन आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि नीति निर्माताओं व विचारकों को ऐसी नीतियां व कार्यक्रमों का सुझाव देना चाहिए जो क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रासंगिक व व्यवहारिक हों। मुख्यमंत्री शिमला के सेंटर आफ पॉलिसी, रिसर्च एवं गवनेंर्स (सीपीआरजी) द्वारा 'डव्लपमेंट मॉडल फॉर हिली स्टेट्स इन न्यू एमर्जिंग इण्डिया' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सम्मेलन में प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री राजनीतिक, विश्लेषक व नीति निर्माता भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाबद्ध एवं सतत विकास द्वारा ही प्रगति एवं समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न केवल लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुसार विकास की बेहतर योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है, बल्कि सतत विकास भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि योजनाकारों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही प्रकार से किया जाए ताकि लोग विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह क्षेत्रीय सम्मेलन हिमालयन क्षेत्र के विकास की रूप रेखा तैयार करने के लिए लाभदायिक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी पहल है और अपनी तरह का ऐसा प्रयास है, जिसमें क्षेत्रीय विषमताओं व पहाड़ी क्षेत्रों की विकासात्मक उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा संभव होगी तथा सम्मेलन में आने वाले सुझावों से नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी और विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने की मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को प्रकृति ने अपार प्राकृतिक संसाधनों तथा स्वास्थ्यवर्धक जलवायु से नवाजा है जिस कारण राज्य पर्यटकों का पसंदीदा गतंव्य बना है। उन्होंने कहा कि इस क्षमता के दोहन के लिए वर्षो से कोई ठोस प्रयास नही किए गए। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि प्रदेश के अनुछुए पर्यटक स्थलों को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को

आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिमला जिला में चांशल को स्कीइंग गतंव्य जबकि मण्डी जिला के जंजैहली को ईको पर्यटन गतंव्य तथा कांगड़ा जिला के बीड़ बिलिंग को पैरा-ग्लाइडिंग गतंव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इनवेस्टर मीट आयोजित करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बैंगलुरु और हैदराबाद में रोड शो के माध्यम से प्रदेश में निवेश की अपार क्षमता को प्रदर्शित कर निवेशकों के साथ सीधा सम्पर्क कर राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में 17 हजार करोड़ की लागत से 159 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिससे राज्य के विकास में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसे वैकल्पिक मंच तैयार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जहां नीति व सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि उन सभी विषयों पर विचार-विमर्श आरम्भ हो जो किन्हीं करणों से आजतक राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं से हमेशा वंचित रहे हैं।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य बड़ा प्रासंगिक है क्योंकि पहाड़ी राज्यों की विकासत्मक जरूरतें अन्यों से अलग-अलग है तथा इन क्षेत्रों ज्यादा धनराशि की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अपने गठन के उपरांत विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ किया जा चुका और बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन से नए विचार सामने आएंगे जो हिमालयाई राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील अम्बेकर ने कहा कि राष्ट्र पिछले कुछ वर्षो में सक्षम और मजबूत नेतृत्व के कारण विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि विकास सभी राजनैतिक पार्टियों के लिए एक ऐजेंड़े के रूप में उभरा है जो कि मजबूत और जीवंत भारत के लिए एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य अगले कुछ वर्षो में सबसे विकसित राज्य बनने का है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक, प्राकृतिक खेती तथा ईको पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय और संस्थानों से स्वरोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

सैंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एण्ड गवरनेंस के निदेशक रामानंद पाण्डे ने मुख्यमंत्री व अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कॉनक्लेव का लक्ष्य हिमालयन क्षेत्र के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है जिसमें पहाड़ी राज्य अपनी नीतियों की चर्चा कर सकें तथा एक-दूसरे के अनुभवों से सिख ले सकें।

5 मार्च तक सभी निजि स्कूल दें अपना वार्षिक शुल्क विवरण: शिक्षा उपनिदेशक

शिमला/शैल। उप शिक्षा निदेशक उच्चतर जसवंत सिंह ने जिला के समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च तथा निजि पाठशालाओं के प्रधानाचार्यो को निर्देश जारी किए हैं कि एच पी पी एस एस पोर्टल पर वर्ष 2018-19 के छात्रवृत्ति आवेदनों का सत्यापन स्कूल स्तर पर 5 मार्च से 20 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी पाठशाला का छात्रवृत्ति मामला पाठशाला स्तर पर सत्यापित नहीं होता है या कोई त्रुटि पाई जाती है तो पाठशाला के मुखिया या छात्रवृत्ति प्रभारी व कमेटी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

साथ ही जिला के सभी निजि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यो को उन्होनें निर्देश दिए हैं कि उनकी पाठशालाओं का शुल्क विवरण, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, वार्षिक शुल्क जो छात्रों से प्राप्त किया जाता है तथा जो सत्र 2019-20 में लिया जाएगा का विवरण, कक्षा बार उप निदेशक कार्यालय को 5 मार्च तक दो प्रतियों में उपलब्ध करवाया जाए।

सभी 12 जिलों या क्षेत्रीय अस्पतालों में बनेंगे नशामुक्ति केन्द्र

शिमला/शैल। सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, संदीप नेगी ने सूचित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तरीय व क्षेत्रीय अस्पतालों में शराब और नशीले पदार्थो की लत की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने नशा निवारण केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। आयोग के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कई घटनाएं विशेष रूप से शराब के सेवन और नशे के अन्य पदार्थो के कारण होती है साथ ही इसके लगातार सेवन से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राज्य के सभी 12 जिला या क्षेत्रीय अस्पतालों में एक नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित व्यक्तिओं का ईलाज हो सके और उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या कानून पर भारी पड़ेगी आस्था
न्यू शिमला के मन्दिर पर आये फैसले से उठी चर्चा

शिमला/शैल। राजधानी के उप नगर न्यू शिमला मे मुख्य सड़क के

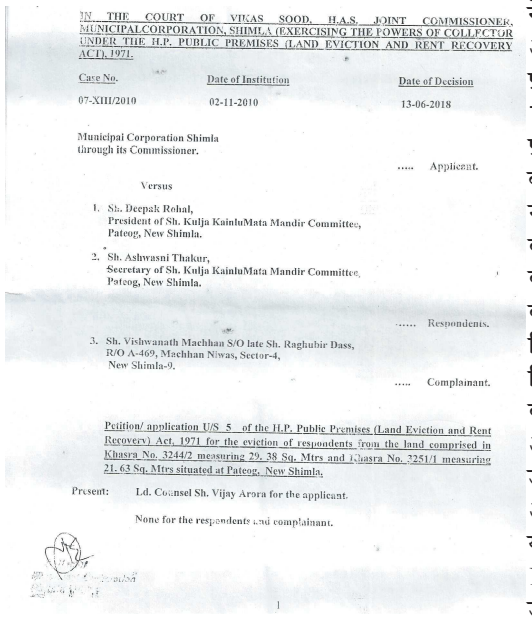

IN THE COURT OF VIKAS SOOD, H.A.S, JOINT COMMISSIONER, MUNICIPALCORPORATION, SHIMLA (EXERCISING THE POWERS OF COLLECTOR UNDER THE H.P. PUBLIC PREMISES (LAND EVICTION AND RENT RECOVERY ACT), 1971.

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
07-XIII/2010	02-11-2010	13-06-2018

Municipal Corporation Shimla
through its Commissioner. ..... Applicant.

Versus

1. Sh. Deepak Rohal,
President of Sh. Kulja KainluMata Mandir Committee,
Pateog, New Shimla.
2. Sh. Ashwasni Thakur,
Secretary of Sh. Kulja KainluMata Mandir Committee,
Pateog, New Shimla. ..... Respondents.
3. Sh. Vishwanath Machhan S/O late Sh. Raghubir Dass,
R/O A-469, Machhan Niwas, Sector-4,
New Shimla-9. ..... Complainant.

Petition/ application U/S 5 of the H.P. Public Premises (Land Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 for the eviction of respondents from the land comprised in Khasra No. 3244/2 measuring 29. 38 Sq. Mtrs and Khasra No. 2251/1 measuring 21. 63 Sq. Mtrs situated at Pateog, New Shimla.

Present: Ld. Counsel Sh. Vijay Arora for the applicant.
None for the respondents and complainant.

किनारे बने दुर्गा मन्दिर को लेकर नगर निगम शिमला के कलैक्टर कोर्ट से आये फैसले के अनुसार यह पूरा मन्दिर

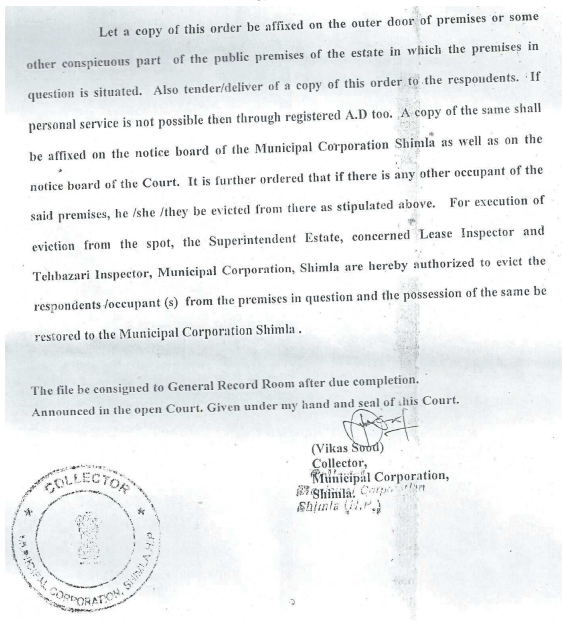

Let a copy of this order be affixed on the outer door of premises or some other conspicuous part of the public premises of the estate in which the premises in question is situated. Also tender/deliver of a copy of this order to the respondents. If personal service is not possible then through registered A.D too. A copy of the same shall be affixed on the notice board of the Municipal Corporation Shimla as well as on the notice board of the Court. It is further ordered that if there is any other occupant of the said premises, he /she /they be evicted from there as stipulated above. For execution of eviction from the spot, the Superintendent Estate, concerned Lease Inspector and Tehbazari Inspector, Municipal Corporation, Shimla are hereby authorized to evict the respondents /occupant (s) from the premises in question and the possession of the same be restored to the Municipal Corporation Shimla.

The file be consigned to General Record Room after due completion.
Announced in the open Court. Given under my hand and seal of this Court.

(Vikas Sood)
Collector,
Municipal Corporation,
Shimla.

COLLECTOR MUNICIPAL CORPORATION, SHIMLA H.P.

सरकार/नगर निगम की जमीन पर बना है। इस जमीन पर मन्दिर बनाने के लिये सरकार/नगर निगम से यह जमीन नही ली गयी है। इस तरह जब मन्दिर निर्माता किसी भी तरह से इस जमीन के मालिक ही नही है तो स्वभाविक है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से इस मन्दिर का निर्माण हुआ है। मन्दिर निर्माण के लिये कोई नक्शा आदि भी निगम से स्वीकृत नही करवाया गया है। नगर निगम की जमीन के खसरा न. 3244/22 में 29.88 वर्ग मीटर और खसरा न. 3251/ में 21.63 वर्ग मीटर भूमि पर मन्दिर का निर्माण हुआ है। इस जमीन की निशानदेही 3-2-2010 को सम्बन्धित नायब तहसीलदार कानूनगो और हल्का पटवारी की देखरेख में हो गयी थी। निशानदेही के वक्त मन्दिर का निर्माण करवाने वाले भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस निशानदेही में यह स्पष्ट रूप से आ गया था कि यह जमीन सरकार/नगर निगम की है। इसी कारण से मन्दिर निर्माताओं ने इस निशानदेही को कोई चुनौती नही दी और यह स्वीकार कर लिया कि यह निर्माण अवैध रूप से सरकारी जमीन पर हो रहा है।

3.2.2010 को निशानदेही हो जाने के बाद नगर निगम ने कलैक्टर की कोर्ट में 2-11-2010 इस संबंध में मामला दायर कर दिया। इस मामले में दीपक रोहाल और अश्वनी ठाकुर को प्रतिवादी बनाया गया। 18-11-2010 को प्रतिवादियों को इस बारे में नोटिस भेजे गये। लेकिन नोटिस के बाद प्रतिवादी इसमें कोई जवाब दायर नही कर पाये। जवाब के लिये सात बार मौका दिया गया लेकिन कोई जवाब नही आया। इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय में आयी एक जनहित याचिका CWP12 No. 08/2018 में उच्च न्यायालय ने कलैक्टर नगर निगम को ऐसे 36 मामलों को तुरन्त निपटाने के आदेश दिये। यह मामले दो माह में निपटाये जाने थे। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों के बाद इस मामले में कारवाई आगे बढ़ी और अन्ततः 13-6-2018 को कलैक्टर नगर निगम ने प्रतिवादियों के खिलाफ फैसला सुना दिया। फैसले में इस निर्माण को गैर कानूनी/अवैध करार देकर इसे गिराने और इस जमीन को नगर निगम को सौंपने के आदेश किये हैं। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये नगर के अधीक्षक एस्टेट, लीज़ निरीक्षक और इन्सपैक्टर तहबाज़ारी की जिम्मेदारी लगाई गयी है।

निगम के कलैक्टर कोर्ट से यह फैसला आये आठ माह का समय हो गया है। कलैक्टर के फैसले पर किसी ऊपरी अदालत का कोई स्टे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस फैसले पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। जब यह मामला 2010 में निशानदेही के बाद कलैक्टर के कोर्ट में दायर हुआ था तब इस मन्दिर का निर्माण चल रहा था और आज तक इसमें कुछ न कुछ काम चला ही रहता है। निशानदेही में ही स्पष्ट हो गया था कि यह जमीन सरकार/नगर निगम की है। इसमें नगर निगम प्रशासन इस निर्माण को कभी भी बलपूर्वक बन्द करवा सकता था जैसा कि अन्य मामलों में अक्सर होता है। लेकिन इस मामले में आज तक ऐसा कुछ भी नही हुआ है। अब भी जून 2018 में आये फैसले पर आजतक अमल न हो पाने से यही सन्देश उभर रहा है कि आस्था कानून पर भारी पड़ती जा रही है।

लोस चुनावों से पहले मुख्यमन्त्री के मीडिया सलाहकार का त्यागपत्र सवालों में
क्या अगला सलाहकार कोई आई.ए.एस. होगा

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो जायेगी। इस परिदृश्य में अभी मुख्यमन्त्री के मीडिया सलाहकार द्वारा त्याग पत्र देकर चला जाना अपने में सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि चुनावों में मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है यह सभी जानते हैं। अभी जयराम सरकार को सत्ता संभाले केवल एक वर्ष हुआ है। मुख्यमन्त्री के अपने सचिवालय में दो सलाहकार एक मीडिया और दूसरा राजनीतिक तैनात रहे हैं। इसी के साथ दो ही विशेष कार्याधिकारी तैनात हैं। यह चारों ही लोग सीधे मुख्यमन्त्री को ही जवाबदेह रहे हैं और इसी कारण से इन्हें मुख्यमन्त्री का विश्वस्त माना जाता है। लेकिन इस एक वर्ष में मुख्यमन्त्री के सचिवालय में किस तरह की कार्यशैली रही है इसका एक नमूना दोनों विशेष कार्यधिकारियों को लेकर लिखे गये खुले पत्र रहे हैं। इसी एक वर्ष में लोक संपर्क विभाग के निदेशक को भी बदल दिया गया। इस तरह निदेशक से लेकर सलाहकार तक का विभाग से हटना विभाग की कार्यशैली से लेकर सरकार की मीडिया नीति तक पर सवाल उठाता है।

सरकार की मीडिया नीति की एक झलक विधानसभा में आये एक सवाल के जवाब में सामने आ चुकी है। इस एक वर्ष में सरकार ने किन अखबारों और दूसरे माध्यमों को कितना विज्ञापन दिया है यह सामने आ चुका है। इसी से सरकार की मीडिया पॉलिसी का खुलासा भी हो जाता है। इस बार जो मीडिया सलाहकार लगाया गया था वह मूलत: एक सक्रिय पत्रकार था। पत्रकारिता छोड़ कर सलाहकार का पद संभाला था। जबकि इससे पहले धूमल और वीरभद्र सरकारों के दौरान जो मीडिया सलाहकार रहे हैं उनका सक्रिय पत्रकारिता से कभी कोई ताल्लुक नही रहा है। ऐसे में फिर यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या जयराम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सलाहकार ला रहे हैं जिसका पत्रकारिता से कोई संबंध न रहा हो। वैसे चर्चा यह भी है कि वीरभद्र शासन की तर्ज पर किसी आईएएस अधिकारी को सेवानिवृति के बाद मीडिया सलाहकार के पदनाम से कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। यह आम चर्चा है कि जयराम सरकार का ज्यादा काम कुछ आईएएस अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। इन अधिकारियों के आगे राजनीतिक नियुक्तियां कोई ज्यादा प्रभावी नही हो पा रही है।

इस परिदृश्य में यह संभावना बढ़ती जा रही है कि शायद कभी निकट भविष्य में सलाहकार का पद नही भरा जायेगा। इस लोकसभा चुनावों में यह भी स्पश्ट हो जायेगा कि जयराम की अफसरशाही कैसे मीडिया को मैनेज करती है। वैसे मीडिया सलाहकार के त्यागपत्र से जयराम सरकार पर लग रहे 'मण्डी प्रेम' के आरोपों पर भी कुछ हद तक जवाब गया है।

चंबा के ठेकेदार को 7 साल की सजा

शिमला/शैल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा ने सड़क निर्माण करने वाले एक ठेकेदार को बैंकों की फर्जी गारंटियों के आधार पर लाखों रुपए बतौर अग्रिम वसूलने के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीजेएम चंबा अभय मंडयाल ने साथ ही दोषी ठेकेदार को आदेश दिए है कि वह लोक निर्माण विभाग को पांच लाख रुपए जुर्माना अदा करे।

विजीलेंस के मुताबिक 15 मार्च 2007 को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भरमौर ने ठेकेदार अरविंद शर्मा को भरमौर में डाहली से साहन के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक करोड़ 99 लाख 30 हजार 722 रुपए का ठेका दिया था। ठेकेदार को यह काम 29 अक्तूबर 2008 तक पूरा करना था।

ठेका मिल जाने के बाद ठेकेदार ने ग्रामीण बैंक भजराडू से तीस लाख की बैंक गारंटी के दस्तावेज देकर मशीनरी की मोबलाइजेशन के लिए लोक निर्माण विभाग से 29 लाख 40 हजार रुपए अग्रिम ले लिए। इसी बैंक से इसी तरह बैंक गारंटी के आधार पर 27 लाख रुपए ले लिए। जबकि इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक गारंटी के आधार पर लोक निर्माण विभाग से 26 लाख रुपए हासिल कर लिए।

बाद में जब लोक निर्माण विभाग ने इन बैंक गारंटियों के दस्तावेजों की छानबीन की तो पता चला कि असल में किसी भी बैंक ने कोई भी गारंटी नहीं दी थी। सारे दस्तावेज जाली पाए गए।

इस पर विभाग के अधिकारियों ने मामला विजीलेंस को सौंप दिया। विजीलेंस ने शुरूआती छानबीन करने के बाद 6 फरवरी 2010 को विजीलेंस के चंबा थाने में धारा 420,467,468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर दिया। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान बैंक गारंटियो से जुड़े तमाम कागजात जाली पाए गए।। विजीलेंस ने सीजेएम चंबा की अदालत में चालान पेश किया व सीजेएम चंबा अभय मंडयाल ने ठेकेदार अरविंद शर्मा को सात साल की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही सड़क निर्माण में देरी के लिए पांच लाख रुपए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भरमौर के खाते में बतौर मुआवजा जमा कराने के आदेश दिए। बाद में विभाग ने इस सड़क के दोबारा टेंडर किए व काम दूसरे ठेकेदार को दिया।

क्या हिमखण्ड में दबे जवानों .....पृष्ठ 1 का शेष

पड़ रही है।

सेना के यह पांचो जवान भी चीन की सीमा पर देश के ही काम से सेना द्वारा भेजे गये थे। वहां पर उसी तरह अचानक हिम खंड हादसे के शिकर हो गये जिस तरह पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान आतंकी हमले के शिकार हुए। पुलवामा में शिकार हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को उनके संबधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार ने भरपूर सहायता दी है। पुलवामा में हिमाचल के कांगड़ा का तिलक राज भी शिकार हुआ है। जयराम सरकार ने तिलक राज की विधवा पत्नी को डीसी ऑफिस धर्मशाला में लिपिक की नौकरी दी है। इसके अलावा और भी कई लोगों ने परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है। लेकिन रायफल मैन राजेश के परिवार को वैसी ही सहायता न तो केन्द्र सरकार और न ही प्रदेश सरकार की ओर से दी गयी है। आज पुलवामा में जो कुछ घटा है उनके फोटो चुनावी सभाओं में लगाये जाने के समाचार सामने हैं। अनचाहे ही यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लेकिन जब पुलवामा के साथ ही किन्नौर के हिमखण्ड में दबे सेना के ही पांच जवानों का हादसा सामने रखा जायेगा तो क्या उसमें अपने आप ही राजनीतिक आचरण पर सवाल नही उठेंगे। क्या यह नही पूछा जायेगा कि इनकी अहमियत कम क्यों?